

बीएचयू की तर्ज पर जनसहभागिता से सुधरेगी लविवि की सूरत

कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की पहल पर एलयू का आर्थिक संकट दूर करने का होगा प्रयास, पूर्व छात्रों से भी ली जाएगी मदद

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तर्ज पर जनसहभागिता से आर्थिक संसाधन जुटाएगा। इसके लिए लविवि के पूर्व छात्रों के साथ ही सामान्य व्यक्तियों से भी सहयोग लिया जाएगा। सीधे साल में प्रवेश कर चुका लविवि अपने छात्रों के माध्यम से यह अभियान चलाएगा। इससे मिली रकम से सीधे वर्ष के आयोजन होंगे। इसके साथ ही लविवि की आर्थिक तंगी दूर करने के साथ ही जनता से सीधे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की पहल पर लविवि में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।

बनारस में महाना मदन मोहन मालवीय ने जनसहभागिता से आर्थिक संसाधन जुटाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लविवि

केनबनियुक्त कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय बीएचयू से ही आए हैं। लविवि की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने इसकी सूरत बदलने के लिए जनसहभागिता को आधार बनाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय इस समय देश के सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालयों में से एक है।

इसके बावजूद यह भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। प्रदेश सरकार ने पिछले 20 साल से ज्यादा समय से लविवि का बजट प्रोजेक्ट कर रखा है। इस वजह से लविवि को पिछले 20 साल से सालाना सिर्फ 34 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि ही मिलती है। जबकि इसके वेतन पर ही करीब 160 करोड़ रुपये सालाना खर्च आता है। इसको देखते हुए

सहभागिता से हो सकता है नया निर्माण

लविवि की रजत जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जेके संस्थान की नींव रखी थी। स्वयं जयंती वर्ष में यहाँ एक छात्रवास का निर्माण किया गया था। जिसे गैलर्डन जुबिली छात्रवास के नाम से जाना जाता है। 100 साल पूरे होने पर भी ऐसा एक निर्माण किया जा सकता है। निर्माण कैसे होगा और इसका आकार क्या होगा, इसका फैसला जनसहभागिता से मिले अनुदान की राशि पर निर्भर करेगा।

लविवि कुलपति ने शिक्षकों से यहाँ के पूर्व छात्रों से संपर्क करने तथा एल्युमिनाई एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए कहा है। अब तक हुए प्रेजेंटेशन में हर

लूटा कर रहा है विशेष दर्जे की मांग

लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन (लूटा) ने 100 साल का होने पर लविवि को विशेष दर्जा देने की मांग की है। लविवि की स्थापना 25 नवंबर 1920 को हुई थी और इसका पहला सत्र 1921 में शुरू हुआ था। लूटा के अनुसार इससे पहले कई राज्यों ने अपने पुराने विश्वविद्यालय को विशेष दर्जा दिया है। प्रदेश सरकार को भी ऐसा करना चाहिए।

हमारे छात्र जुटाएंगे धन

कुलपति की पहल पर लविवि के पूर्व छात्रों के साथ ही सामान्य जन को लविवि के लिए सहयोग करने के लिए कहा जाएगा। हमारे विद्यार्थी उनके पास जाएंगे। जनसहभागिता के माध्यम से लविवि शताब्दी वर्ष के आयोजन के धन जुटाएगा।

परिसर का भ्रमण कर बीसी ने वास्तविक स्थिति देखी

परिसर का भ्रमण कर बीसी ने वास्तविक स्थिति देखी



लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार संभालने के बाद रविवार को छुट्टी के दिन प्रो. आलोक कुमार राय ने परिसर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की भौगोलिक स्थिति और वास्तविक अवस्था देखी। इस दौरान उनके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. नीरज जैन व अन्य पदाधिकारियों के साथ ही कार्य अधीक्षक तथा प्रॉक्टर प्रो. दिनेश कुमार और प्रवक्ता संजय मेधावी समेत अन्य शिक्षकगण मौजूद थे।

एलयू को मिले 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

उच्च शिक्षा, मानव स्वास्थ्य, साइबर वर्ल्ड आदि विषयों पर शोध के लिए मिलेंगे 1.03 करोड़ रुपये

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में 13 नये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी मिल गई है। इन सेंटर के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक करोड़ तीन लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इन सेंटरों के माध्यम से ग्रा मी ण औद्योगिकरण, मानव स्वास्थ्य, गांधीजी के विचार, सायबर वर्ल्ड, शहर में पानी की स्थिति आदि पर शोध होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने लविवि की ओर से दिए गए 25 प्रस्तावों में से 13 पर अपनी मुहर लगा दी है। इनका बजट स्वीकृत हो गया है। अनुदान आते ही इन पर काम शुरू हो जाएगा।



विषय की ओर से दिए गए 25 प्रस्तावों में से 13 पर उच्च शिक्षा विभाग ने लगाई मुहर

इनको मिली मंजूरी :

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस- शिक्षक-अनुदान राशि

- **अप्लाइड इकोनॉमिक्स :** उत्तर प्रदेश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण और सामाजिक आर्थिक बदलाव- प्रो. आरके माहेश्वरी- 15 लाख रुपये
- **बायोकेमिस्ट्री :** इनवायरमेंटल इंफैक्ट एंड ह्यूमन हेल्थ- प्रो. सुधीर मेहरोत्रा और डॉ. मीनल गर्ग- 9 लाख रुपये
- **एजुकेशन :** स्केल बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम- प्रो. अमिता बाजपेयी- 8 लाख रुपये

लविवि में पिछले वित्तीय वर्ष में 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर मुहर लगने के बाद इस साल 13 नये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होने का रास्ता खुल गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए

- **जियोलाॅजी :** जियो हायड्रोलॉजिकल एसेसमेंट- प्रो. अजय मिश्रा- 8 लाख रुपये
- **जियोलाॅजी :** अरबन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम- प्रो. विभूति राय- 8 लाख रुपये
- **जियोलाॅजी :** स्लोप एस्टेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन इन हिली एरिया- डॉ. राजेश सिंह- 4 लाख रुपये
- **लॉ :** गांधी विजन- डॉ. अनुराग कुमार श्रीवास्तव- 5 लाख रुपये
- **फिजिक्स :** इनोवेशन मैटेरियल्स एंड साइबर वर्ल्ड, प्रो. राजीव मनोहर- 10 लाख रुपये

शासन ने अपनी स्वीकृत दे दी है। इन सेंटर के माध्यम से बालिकाओं पर होने वाली हिंसा, मछलियों के उत्पादन, महिला पुलिस की भूमिका, स्कूलों में समेकित शिक्षा के विशेष सेंटर आदि पर शोध होगा। इसकी

- **लोक प्रशासन :** क्राइम ऑगेंस्ट विमेन रोल ऑफ विमेन पुलिस- डॉ. श्रद्धा चंद्रा- 5 लाख रुपये
- **सोशल वर्क :** वायलेंस ऑगेंस्ट गर्ल्स इन स्कूल- प्रो. अनूप भारतीय और डॉ. गरिमा सिंह- 10 लाख रुपये
- **सांख्यिकी :** डाटा एनालिसिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट- प्रो. शोला मिश्रा- 8 लाख रुपये
- **जूलॉजी :** मॉलीक्यूलर एनालिसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज- प्रो. मोनीषा बनर्जी- 8 लाख रुपये
- **जूलॉजी :** फिश प्रोडक्टिविटी- डॉ. मनोज कुमार- 5 लाख रुपये

रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। एक साल से ज्यादा वाले प्रोजेक्ट के लिए अगली किस्त पहले साल की राशि के खर्च तथा उपभोग प्रमाण आदि भेजने पर शासन की ओर से स्वीकृत की जाएगी।